

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

**1. Case No 9251/2022 Shri Deepanshu Sahu Owner, 305, Gohalpur, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 3.20 ha. (87504 Cum per annum) (Khasra No. 18, 19, 24), Village - Manegaon, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) Env. Global Management and Engineering Consultant International, Jaipur (Raj.)**

This is case of Stone & Murrum. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 18, 19, 24), Village - Manegaon, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) 3.20 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2353 दिनांक 30/07/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 14 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 31.33 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

आवेदित क्षेत्र के संबंध में वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, जबलपुर के क्रमांक 2510 दिनांक 24/07/2018 में आवेदित क्षेत्र आर.एफ. 173 से 118 मीटर दूर होना बताया गया है। संयुक्त जॉच प्रवितेदन 15/08/18 में आवेदित क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 173 की सीमा से 118 मीटर दूर बताया गया है। संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19/11/20 अनुसार उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, बैठक दिनांक आवेदित क्षेत्र में वन सीमा की ओर से फैंसिंग लगाये जाने की शर्त पर सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 500 मीटर पर रोड़ है तथा पूर्वी दिशा में ही 310 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी भाग में पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराना माइंड आउट पिट है एवं लीज हमें इसी अवस्था में स्वीकृत हुई है तथा पिट को सरफेस में दिखा गया है। चूँकि खदान के पूर्वी भाग में पानी भरा हुआ है, अतः डी-वाटरिंग योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 500 मीटर पर रोड़ है तथा पूर्वी दिशा में ही 310 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. चूँकि खदान के पूर्वी भाग में पानी भरा हुआ है, अतः डी-वाटरिंग योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आंवटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्वेशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
9. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

2. **Case No 9252/2022 M/s Vrindavan Construction, Partner, Shri Arun Agrawal S/o Late Shri R.P.Agrawal, 250, Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Dist. Bhopal, MP. Environment Clearance for Proposed at Proposed "Sage Golden Spring" Residential Apartment located at Khasra No. - (10/1, 12, 13, 14, 15), (10/2/1, 12, 13, 14, 15), 11/1, (16/1, 18, 21), (16/2, 18, 21) 17/1/1, 17/1/2, 17/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 28/1/1, 28/1/2, 28/2/1, 28/2/2, 29/1/1, (A) 29/1/1 (B) 29/1/2/1, 29/1/2/2, 84/1/1, (84/2/1, 85, 86/1), 84/2/2, 86/2, Village – Damkheda, Patwari Halka No. 21, Tehsil – Huzur & District – Bhopal (M.P.). Total Plot Area – 47170.00 Sq.mtr. (4.717 ha.), Built Up Area - 98714.54 square meter ha., Cat. - 8(a). Building and Construction projects. Env. Con. -Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur, (Rajasthan).**

This is case of Environment Clearance for Construction of "M/s Vrindavan Construction is developing "Sage Golden Spring" Residential Apartment Located at Village: Damkheda, Patwari Halka No. 21, Tehsil – Huzur & District – Bhopal, Madhya Pradesh on a land admeasuring 47,170 Square meter (4.717 Ha).

The case was presented by Env. Consultant Shri G.K. Mishra, Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur, (Rajasthan) and Shri Sanjay Gupta on behalf of PP. During presentation, it was observed as per Google image that PP has started constructed at site without prior Environment Clearance and therefore, its a violation of Environment Protection Act, 1986. PP submitted that they have applied under violation category. PP submitted following salient features of the project:

**Area Statement:**

S. No.	Description	Proposed	Units
<b>AREA DETAILS</b>			
1.	Total land Area (4.717 Ha)	47,170	Sq m
2.	Road Area Surrendered	4,849.94	Sq m
3.	Net plot Area	42,320.06	Sq m
4.	Open Park	4658.50	Sq m
5.	Built up Area	98,714.54	Sq m
<b>WATER AND WASTE WATER REQUIREMENTS</b>			
7.	Total Fresh Water Requirement	540	KLD
8.	Wastewater Generation	456.111	KLD
<b>PARKING</b>			
9.	Multiplex/Shopping Mall	201	ECS
10.	Flats (G+1)	576	ECS
11.	Plots	129	ECS

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

<b>POWER</b>			
<b>12.</b>	Total Power Requirement	3500	KW
<b>13.</b>	Power Source	Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB).	
<b>14.</b>	Total DG Set proposed	(1 x 600) & (3 x 500)	KVA
<b>WASTE GENERATION</b>			
<b>15.</b>	Municipal Solid Waste Generation	1.50	TPD

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8<sup>th</sup> March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8<sup>th</sup> March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits.
2. On the south-west side of the project area, a natural drain is in existence which shall not be diverted in any case. Alos its protection plan with 30 meters setback (as no development zone) from HFL shall be discussed in the EIA report.
3. If any demolition works are proposed, the details of C&D wastes shall be properly addressed in the EIA report.
4. No tree is falling proposed for which a written commitment shall be submitted.

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

5. Water and waste water details (water requirement for residents, staffs and for floating population etc.) shall be provided as suggested by the committee during TOR presentation.
6. Green Building concepts (Status of GRIHA rating or IGBC rating ) shall be adopted (minimum silver rating as submitted during TOR presentation) and their details shall be submitted with EIA report.
7. One common convenience facility shall be provided for supporting staff and details shall be discussed in the EIA report.
8. Status report of construction work place so far, possession given to how many families etc.
9. Detailed plantation scheme with proposed species shall be discussed in the EIA report.
10. Furnish details of CO<sub>2</sub> emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
11. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
12. Fire NOC to be taken from the concerned department and submitted with EIA.
13. Under energy conservation plan detail-out solar light erection panels.
14. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
15. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
16. Land acquisition status, R & R details (if any).
17. Baseline environmental study for ambient air (PM<sub>10</sub>, PN<sub>2.5</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
18. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
19. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
20. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
21. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
22. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

23. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
24. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
25. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
26. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.

**3. Case No 9212/2022 Ms. Payal Binnen, 81, Rajendra Nagar, Dist. Ratlam, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (19000 Cum per annum) (Khasra No. 3/1/1/1), Village - Sawaliyarundi, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/1/1/1), Village - Sawaliyarundi, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 583वीं दिनांक 30/06/22 एवं 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

**4. Case No 9219/2022 Shri Shubhash Kirar, Owner, 3/16, Aishbag, Near Manshi Hospital, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Basalt Stone Quarry in an area of 3.970 ha. (19665 Cum per annum) (Khasra No. 1012), Village - Kasba, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) EIA Consultant: Cognigance Research India (P) Ltd., Noida (UP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1012), Village - Kasba, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) 3.970 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 30/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार सुश्री स्वाती नामदेव उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1278 दिनांक 13/01/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 19.611 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पूर्व में क्रमशः 65 मीटर पर कच्चा रोड़ है तथा उत्तर दिशा में 195 मीटर पर शेड है, अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पूर्व में क्रमशः 65 मीटर पर कच्चा रोड़ है तथा उत्तर दिशा में 195 मीटर पर शेड है, अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये।
2. खदान के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र से लीज के अंदर से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये।

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इम्पेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओवर बर्दन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**5. Case No 9253/2022 M/s Madhya Pradesh Minerals Supply Company, Ward No. 8, Village - Jaitwara, Dist. Satna, MP Prior Environment Clearance for Ochre, white Earth, & Bauxite Mine in an area of 5.005 ha. (Bauxite - 44414 Tonne per annum, Ochre - 4224 Tonne per annum, OB - 7634 Tonne per annum) (Khasra No. 9, 4/1, 5, 7/1, 7/2, 7/3 & 50), Village - Ghatania , Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP)**

This is case of Ochre, white Earth, & Bauxite Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 9, 4/1, 5, 7/1, 7/2, 7/3 & 50), Village - Ghatania , Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 5.005 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खनिज बाक्साइट (लीज एरिया 5.005 हे.) होने के कारण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर आबादी / बसाहट है तथा लीज क्षेत्र के पूर्वी भाग से होकर कच्चा रास्ता निकल रहा है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये । साथ ही प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊंचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त



## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर आबादी / बसाहट है तथा लीज क्षेत्र के पूर्वी भाग से होकर कच्चा रास्ता निकल रहा है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आवेदित स्थल टाईगर मूवमेंट एरिया से बाहर है, के संबंध में वन मंडला अधिकारी (डी.एफ.ओ.) का प्रमाण-पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व केंशरो का क्यूमिलेटिव इम्पेक्ट असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अध्ययन के साथ किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**6. Case No 9254/2022 Shri Rakesh Agrawal, Owner, G-11, Chouraha, Scheme No. 94, Dist. Indore, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 639, 645, 648) near Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, MP Environment Consultant Apex Mintech Udaypur (Rj.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 639, 645, 648) near Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, (MP) 3.20 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

आज दिनांक 30/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 866 दिनांक 06/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 32.750 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 360 मीटर, उत्तर दिशा में 170 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 170 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में 03-04 पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth सहित फोटोग्राफ एवं ड्रोन विडियोग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान के उत्तर-पूर्वी दिशा में 750 मीटर पर तालाब है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। खदान के गूगल इमेज के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2019 से उत्खनन कार्य किया जा रहा है। प्रकरण के साथ प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना एवं सरफेस मैप पर पिट का विवरण दर्ज नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको यह खदान इसी स्थिति में मार्च, 2022 में स्वीकृत हुई है एवं उनके द्वारा उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। चूँकि अनुमोदित खनन योजना एवं सरफेस मैप पर पिट का विवरण दर्ज नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ माईनिंग अधिकारी यह प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा कि इस खदान पर किया गया उत्खनन कार्य उसके द्वारा नहीं किया गया है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 360 मीटर, उत्तर दिशा में 170 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 170 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान में 03-04 पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth सहित फोटोग्राफ एवं ड्रोन विडियोग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर-पूर्वी दिशा में 750 मीटर पर तालाब है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. खदान के गूगल इमेज के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2019 से उत्खनन कार्य किया जा रहा है। प्रकरण के साथ प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना एवं सरफेस मैप पर पिट का विवरण दर्ज नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको यह खदान इसी स्थिति में मार्च, 2022 में स्वीकृत हुई है एवं उनके द्वारा उत्खनन कार्य नहीं किया गया

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

है। चूँकि अनुमोदित खनन योजना एवं सरफेस मैप पर पिट का विवरण दर्ज नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ माईनिंग अधिकारी यह प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा कि इस खदान पर किया गया उत्खनन कार्य उसके द्वारा नहीं किया गया है।

5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
8. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
10. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
11. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

**7. Case No 8624/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Signatory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.082 ha. (70000 cum per annum) (Khasra No. 1214, 1215), Village - Pasan, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1214, 1215), Village - Pasan, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 6.082 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

- 8. Case No 8625/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 164), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 164), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 6.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

- 9. Case No 8626/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.50 ha. (32000 cum per annum) (Khasra No. 1763, 95/1), Village - Gobri, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1763, 95/1), Village - Gobri, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 6.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

**10. Case No 8627/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Signatory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.664 ha. (67968 cum per annum) (Khasra No. 1), Village - Chakaghat, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1), Village - Chakaghat, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 5.664 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**11. Case No 9196/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.10 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 1), Village - Kutiya, Tehsil - Rajnagar, Dist. Chhatarpur (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1), Village - Kutiya, Tehsil - Rajnagar, Dist. Chhatarpur (MP) 2.10 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

**12. Case No 9197/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 4.0 ha. (35000 Cum per annum) (Khasra No. 1400), Village - Sadkar, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1400), Village - Sadkar, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**13. Case No 9198/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 1.40 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 701), Village - Rampur Kurra, Tehsil - Chhatarpur, Dist. Chhatarpur (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 701), Village - Rampur Kurra, Tehsil - Chhatarpur, Dist. Chhatarpur (MP) 1.40 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**14. Case No 9039/2022 M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd, Shri Vaibhav Rai, Director, 37 - 38, Lasudia Mori, Dewas Naka, A.B. Road, Dist. Indore, MP Prior Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawer, Dist. Indore, (MP) Env. Consultant M/s. Global Management And Engineering Consultants International, Jaipur (Raj.).**

This is case of Prior Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawer, Dist. Indore, MP. Cat. - 8(a) Building and Construction Projects.

Earlier this case was scheduled in the SEAC 556<sup>th</sup> meeting dated 02.03.2022, for presentation and discussion in 556<sup>th</sup> SEAC dated 02/03/2022 wherein ToR (Violation) was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by the Mr. Sameer Khedkar PP and their Shri G.K.Mishra Env. Consultant from M/s. Global Management And Engineering Consultants International, Jaipur (Raj.), wherein PP submitted that the proposed project is a Development of Commercial Warehouse, with total plot area of 1,30,780.00 sqm., and planning area is 1,29,942.63 sqm. The proposed built-up area of the proposed project will be 56,156.00 sqm. Construction work has been completed and covered till 55% of built-up area owing to unawareness of the EIA Notification and its amendments and falls under the purview of the EIA Gazette Notification dated 08.03.2018, amending the Notification dated 14<sup>th</sup> March 2017. but actual at site presently 6 to 8 % area has been finished for working on rest covered area only prefabricated installations have been done. This report has been prepared in compliance to Gazette Notification dated 08.03.2018, amending the Notification dated 14<sup>th</sup> March 2017 including assessment on ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan.

**The salient features of the project:**

- The project “Development of Commercial Warehouse” located at Survey No. 53, Khasra No. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66/1, 66/2, 67/1, 75/1, 75/2, 75/3 etc. at Village- Pirkaradiya, Tehsil- Sewer, District- Indore, Madhya Pradesh, India. Area of Project is 1,30,780.00 m<sup>2</sup> (1.30 Ha.) and it offers Warehouse-1, Warehouse-2, & Warehouse-3.
- The proponent has been constructed structure of 1 & ½ units of warehouse namely Warehouse 1 & 2. 3rd unit is not constructed or started on ground.

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

- Field studies has been referenced nearby project study which is almost attached to the project site for the period 1st December 2020 to 28th February 2021 (Winter Season) to determine the existing conditions of various environmental attributes.

### Chronology of the Project

Application Submission to SEIAA	28-02-2022
TOR Approved by SEIAA	17-03-2022
Final EIA Report Submission to SEIAA	09-05-2022
<b>Total Built-up Area</b>	<b>56,156 sqm</b>
Build-up Area of Warehouse-1	20,520 sqm
Build-up Area of Warehouse-2	19,836 sqm
Build-up Area of Warehouse-3	15,800 sqm

### ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN –

S. No.	Particulars	Total cost	Recurring Cost (Annual)	Remarks
1	Sewage Treatment Plant	₹ 9,40,600	₹ 1,50,000	AMC + Operator cost
2	Storm water drainage/ RWH Pits with boring / roof top channel	₹ 52,00,000	-	-
3	Solid Waste Management	₹ 1,38,000	₹ 74,000	Wastebin + Manpower
4	Environmental Monitoring	₹ 2,00,000	₹ 2,00,000	
5	DG set Stack	₹ 9,38,600	₹ 2,04,600	DG cost + permission + challan + diesel
6	Horticulture & Green Belt	₹ 2,40,000	₹ 1,50,000	Plants + Gardner
7	Fire Fighting	₹ 3,84,00,000	-	Fire Hydrants
8	Solar Energy	₹ 8,11,500	₹ 15,000	Solar Plant + AMC
9	Health, Safety & Miscellaneous	₹ 37,000	₹ 11,000	Safety Shoes + Safety Jackets + Safety Helmet + Safety Signages
10	Water supply / Tanks & Services	₹ 85,85,520	₹ 25,00,000	Borewell (Drill to Motor Fixing) + Underground Tanks + Tanker Water Cost
11	Electrical development	₹ 2,93,00,000	-	
<b>Total</b>		<b>₹ 8,47,91,220</b>	<b>₹ 3,04,600</b>	

### REMEDIATION PLAN:

S. No.	Aspects	Amount (INR - Lakh)
1.	Capital	7.7
2.	Recurring	4.05
<b>Total</b>		<b>11.75</b>



## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

All remediation budgets will be implemented for additional plantation and installation of solar on grid system at site.

### Remediation Plan

S. No.	Activity	Total Cost (CR)	Amount Spent (CR)
1.	Structural Cost	14.39	7.00
2.	Inside Fabrication System	16.84	0.20
3.	Ventilation System (Design & Installation)	14.39	0.50
4.	Firefighting System (Installation & Water Storage Tank)	22.46	0.50
5.	Installation of Mechanical Multi Storage	19.65	0.25
6.	Other Development Cost Including Land, Water, Sewage, electricity & landscaping	378.26	1.50
Total		126.00	9.95

The project development cost Rs. 126 Crores has been estimated. The capital and the recurring expenditure on the item wise activities for environment management plan are as follows:

Description	Cost
Capital	8,47,91,220
Recurring (Operational Phase Maintenance Cost)	3,04,600
<b>Total</b>	<b>8,50,95,820</b>

PP, M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd, Shri Vaibhav Rai, Director, 37 - 38, Lasudia Mori, Dewas Naka, A.B. Road, Dist. Indore has proposed to submit a guarantee of Rs. 11.75 lakh (including capital Rs. 7.7 Lakh and 4.045 Lakhs as recurring cost for this project) towards Remediation Plan. In addition, expenditure already incurred on implementation of EMP is Rs. 8,50,95,820/-. After presentation and discussions following information was asked to submit by the PP:

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

1. Revised plantation scheme with nos. as 5000 nos. & species with PP's commitment that the plantation shall be carried in association of forest department as suggested by the committee.
2. PP shall submit CA authenticated certificate wrt to remediation cost assessment.
3. Revised CER with enhanced appropriate budget including drinking water facility in the Pipilya Khedi village and distribution of Medical equipments in the nearby village's PHC (or need based after asking concerned doctor in the village PHC).
4. Carbon foot prints wrt vehicular movement.
5. PP's commitment that 20% power shall be solar based.
6. Address worst case scenario wrt MSW generation & their disposal.

PP submitted the reply on above issues vide letter dated 19/05/2022 and same was placed before the committee. Committee evaluated the reply and found satisfactory and acceptable and recommends that PP shall deposit the bank guarantee with three years validity of Rs. 11.75 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA as per the procedure laid down in the MoEF&CC Notification dated 08/03/2018.

Further, this being a violation case for which Ministry of Environment Forests & Climate Change vide its OM dated 28/01/2022, has reinstated the Standard Operating Process (SOP) dated 15/07/2021 as per the order dated 09/12/2021 of Hon'ble Supreme Court of India to deal with the violation cases. Penalty provisions as per para 12 (i) of the notification will be applicable i.e. 1% of the total project cost incurred upto date. PP has submitted a certificate on cost incurred of Rs. 9.95 Crore. As the operation has not started the penalty provision works out to be Rs. 9.95 lakh.

The EIA/EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawer, Dist. Indore, (MP). [Total plot area 1,30,780.00 sqm., Planning area 1,29,942.63 sqm., proposed built-up area 56,156.00 sqm.] subject to deposit bank guarantee of Rs. 11.75 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA, Penalty @ 1% of the total project cost incurred upto the date of filling of application i.e. Rs. 9.95 lakh as per clause 12 a.i. of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act, 1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21 with following conditions:

**I. Statutory compliance:**

- i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project (if any).
- ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife (if applicable).
- iii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (in case of the presence of any schedule-I species in the study area) .
- iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee
- v. NOC shall be obtained from National Commission of Seismic Design Parameters (NCSDS) of CWC (if applicable).
- vi. Necessary approval of CEA shall be obtained for those projects having the project cost more than Rs. 1,000 crore (if applicable).

**II. Air quality monitoring and preservation**

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. Diesel power generating sets (1 x 125 + 1 x 160 + 2 x 62.5 + 1 x 20 + 1 x 25 KVA (DG Sets) proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel.

The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from DG set ( $1 \times 125 + 1 \times 160 + 2 \times 62.5 + 1 \times 20 + 1 \times 25$  KVA (DG Sets) shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

### **III. Water quality monitoring and preservation**

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during construction phase are as follows :

S. No.	Particulars	Water Requirement	Wastewater Generation (KLD)	
			Quantity	Remarks
1	Domestic Water for workers (50 @ 45lpcd)	2.25	1.9125	85% Wastewater will be disposed into Septic Tank
2	Dust Suppression	2	1.6	Losses 20% loss on washing; rest will be collected and reused for curing after necessary treatment
3	Washing of Construction Equipment	2	2	-
4	Curing	2	2	Losses
<b>Total</b>		<b>8.25 (KLD)</b>	<b>7.5125</b>	-

- iv. The total water requirement during operation phase are as follows

S. No.	Item Description	Number of Persons/Seats & Area	Water Requirement/ head (litres)	Total water Requirement (litres)
<b>A</b>	<b>Fresh Water Requirement</b>			
1	Staff	200	25	5000
2	Visitor	800	10	8000
<b>Sub Total of A</b>				<b>13000</b>
<b>B</b>	<b>Flushing Water</b>			
1	Staff	200	20	4000

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

2	Visitor	800	5	4000
<b>Sub Total of B</b>				<b>8000</b>
<b>C</b>	<b>Treated Effluent Water Requirement - Misc. Uses</b>			
1	Landscaping	5555.75	1/sqm	5555.75
<b>Sub Total of C</b>				<b>5555.75</b>
<b>Total water requirement (A+B+C)</b>				<b>26555.75</b>
<b>Or says 26.55 say 27 KLD</b>				

- v. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be to monitor to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- vi. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vii. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- viii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- ix. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- x. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- xi. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xii. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage

and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

- xiii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fire water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiv. For rainwater harvesting, 09 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about  $951\text{m}^3/\text{hr}$ . Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.
- xix. 19.05 KLD will be the total wastewater generated, which will be treated in the STP of 25 KLD. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
- xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 25 KLD capacity and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban

Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

#### **IV. Noise monitoring and prevention**

- i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient noise standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time .

#### **V. Energy Conservation measures.**

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

#### **VI. Waste Management**

- i. During the operation phase, waste is comprised of domestic as well as landscape waste. The solid waste generated from the project is mainly domestic waste and estimated quantity of the waste is approx. 170.27 kg per day (@ 0.15 kg per capita per day for the visitor, 0.25 kg per capita per day for the staff members, 0.2 kg per aces for landscape). Following arrangements has been made at the site in accordance with Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 and amended Rules, 2016 and the electronic waste is managed as per the guidance of E-waste (Management and Handling) Rules 2016.
- ii. Any additional muck generated from remaining activities, will be disposed off at nearby villages with due consent of local administration/gram panchayat. As the pipeline passes along the villages, villages will fall within



- 1-5 Km along the route of pipeline.
- iii. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

## **VII. Green Cover**

- i. Total 5000 trees (1000 plants in the project boundary & 4000 plants in the other areas as per submitted proposal) shall be planted as greenbelt development through CCF, Social Forestry or by concerned DFO or any technically competent agency in the first year.
- ii. Not tree can be felled/transplant.
- iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover such as Pipal, ficus, Kadamb, Putranjeeva etc are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.
- v. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

## **VIII. Transport**

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
  - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
  - b. Traffic calming measures.
  - c. Proper design of entry and exit points.

d. Parking norms as per local regulation.

- ii. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

#### **IX. Human health issues**

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

#### **X. EMP & CER**

- i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.

- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- v. PP has proposed 11.75 Lakh (including capital Rs. 7.7 Lakh and 4.045 Lakhs as recurring cost) for this project and PP, M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd, Shri Vaibhav Rai, Director, 37 - 38, Lasudia Mori, Dewas Naka, A.B. Road, Dist. Indore has proposed to submit a guarantee with three years validity of Rs. 11.75 lakh towards Remediation Plan. In addition, expenditure already incurred on implementation of EMP is Rs. 8,50,95,820.00/-.
- vi. As per OM dated 07/07/21 Penalty @ 1% of the total project cost incurred upto the date of filling of application i.e. Rs. 9.95 lakh as per clause 12 that is of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act, 1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.
- vii. For this project PP has proposed Rs 11.00 Lakh as Corporate Environment Responsibility (CER):

Nutritious food for nearby Aganwadi center	INR 2.0 lakhs
--	---------------

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

Drinking water facility for nearby areas	INR 2.0 lakhs
Provision for donation of medical equipment at nearby Public Health Centers (PHC) of near by areas.	INR 2.0 lakhs
Plantation as suggested by the registrar of Dr. B R Ambedkar University , Indore, MP.	INR 5.0 lakhs

## **XI. Human health issues**

- i. Resettlement & Rehabilitation plan be implemented in consultation with the State Govt. as approved by the State Govt.
- ii. Budget provisions made for the community and social development plan including community welfare schemes shall be implemented in toto.
- iii. Preventive measures viz. fuming and spraying of mosquito control shall be done in and around the labour colonies, affected villages, stagnated pools, etc. Provisions be made to not to create any stagnated pools to avoid creation of breeding grounds of the vector borne diseases
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Labour force to be engaged for construction works shall be examined thoroughly and adequately treated before issuing them work permit. Medical facilities shall be provided at the construction sites.
- vi. Early Warning Telemetric system shall be installed in the upper catchment area of the project for advance intimation of flood forecast.
- vii. Emergency preparedness plan be made for any eventuality of the dam failure and shall be implemented as per the Dam Break Analysis.

## **XII. Miscellaneous**

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

- Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
  - iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
  - v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

The case was discussed in the 572<sup>nd</sup> SEIAA meeting dated 19/05/22 wherein certain observations are made by them and case is referred back to SEAC for re-appraisal vide letter no. 676-77/SEIAA/22 dated 06-06-22. The case was discussed in the meeting wherein it was deliberated that the case was appraised on the basis of information provided by the PP during presentation and documentary evidences provided such as damage assessment and remediation plan alongwith the certificate of CA. Since SEIAA has referred back this case for re-appraisal, committee decided to carryout the site visit for verification of facts submitted by PP by a committee member and based on the report, case shall be re-appraised in upcoming SEAC meetings.

The site visit of this project (Case No 9039/2022 M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd, Shri Vaibhav Rai, Director, 37 - 38, Lasudia Mori, Dewas Naka, A.B. Road, Dist. Indore, MP Prior Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawer, Dist. Indore, (MP) was carriedout by SEAC members on dated 25/06/22 and the report was submitted same day and same discussed in today's meeting. The site visit report submittd by the members is as follows:

- This is case of Prior Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawer, Dist. Indore, MP. Cat. - 8(a) Building and Construction Projects under violation category.

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 30 जून 2022

- The project “Development of Commercial Warehouse” located at Survey No. 53, Khasra No. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66/1, 66/2, 67/1, 75/1, 75/2, 75/3 etc. at Village- Pirkaradiya, Tehsil- Sewer, District- Indore, Madhya Pradesh, India. Area of Project is 1,30,780.00 m<sup>2</sup> (1.30 Ha.) and it offers Warehouse-1, Warehouse-2, & Warehouse-3.

➤ **Chronology of the Project**

Application Submission to SEIAA	28-02-2022
TOR Approved by SEIAA	17-03-2022
Final EIA Report Submission to SEIAA	09-05-2022

➤ **SITE VISIT**

The site visit was carried out on 25/06/2022 by Dr. Anil Sharma, Member SEAC and Prof. (Dr.) Alok Mittal, Member SEAC with Dr. Abhaya K. Saxena, Senior Scientific Officer, MPPCB, Bhopal. During site visit Shri G. K. Mishra, Environment Consultant, M/s Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur (Rajasthan) and representative from M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd were present with their supporting staff.

➤ **OBSERVATION**

- ✓ During Site visit MPSEAC Team observed that out of proposed three warehouses namely Warehouse-1, Warehouse-2 and Warehouse-3 structures of two warehouses i.e. Warehouse -1 and Warehouse-2 have been erected.
- ✓ Works related to Warehouse-3, landscaping, parking area and other facilities such as STP, fire fighting arrangements with water storage tanks, RWH, Staff convenience facilities & Shelter, electrical works etc., are yet to be initiated.
- ✓ Both the erected warehouses were physically inspected for the purpose of assessing the constructed value.
- ✓ During inspection it was observed by the committee that Warehouse-1 has been put to operations and given to an agency for use wherein only basic facilities such as emergency lightning arrangements & temporary cabins

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

have been provided. Ventilation and other facilities such as mechanical racking with lifts, partitions are yet to be provided.

- ✓ In Warehouse-2 only structure and ventilation is completed. Other works such as mechanical racking with lifts, partitions, electrical, fire fighting etc is yet to be put in place.
- ✓ Both Warehouse-1 & Warehouse-2 have been erected about 01 meter above the ground with 2.4 meters brick Masonry work.
- ✓ PP submitted that at the time of presentation we have submitted CA certificate for valuation of work done which was for Rs. 09.95 Cr.
- ✓ The review of the drawings and subsequent market analysis, the cumulative constructed value of both the warehouses referred above quoted INR 9,95,00,000/- [Rupees Nine Crore Ninety Five Lacs Only] as per the market analysis carried out by M/s PMKG Techno-Management Consultancy LLP, an IBBI Registered valuer with following analysis of the presently constructed area:

Total Built-up Area	56,156 sqm	Details	Status & Remarks
Build-up Area of Warehouse-1	20,520 sqm	<p><b>Approximate Area:</b> 20,520 Sqm,  <b>Approximate Length/Depth:</b> 270 meters  <b>Approximate Width:</b> 76 meters  <b>Height of Structure:</b> Nearly 12 (Twelve) meters  <b>Height of Brick Masonry Wall:</b> 2.4 meters  <b>Plinth Height:</b> 1 meter</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Only structure completed. Ventilation system yet to be installed.</li> <li>• Mechanical racking and fabrication are yet to be installed.</li> <li>• Fire installation is partially done.</li> <li>• RWH system is yet to be installed,</li> <li>• Drainage is partially completed.</li> <li>• Electrification work is majorly completed.</li> </ul>

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

<b>Build-up Area of Warehouse-2</b>	<b>19,836 sqm</b>	<b>ApproximateArea:19,836Sqm,</b> <b>ApproximateLength/Depth:261meters</b>  <b>ApproximateWidth:76meters</b>  <b>HeightofStructure:Nearly12 (Twelve)meters</b>  <b>HeightofBrickMasonryWall:2.4meters</b>  <b>PlinthHeight:1 meter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Only structure completed. Ventilation system yet to be installed.</li> <li>• Mechanical raking and fabrication are yet to be installed.</li> <li>• Fire installation is partially done.</li> <li>• RWH system is yet to be installed,</li> <li>• Drainage is partially completed.</li> </ul> <p>Electrification work is majorly completed</p>
<b>Build-up Area of Warehouse-3</b>	<b>15,800 sqm</b>	<b>Yet to be started</b>	<b>No work on ground</b>
<b>Landscaping, parking,</b>	<b>Development yet not started</b>		

- ✓ The above status was verified by the MPSEAC team during the site visit.
- ✓ The break-up of valuations of above mentioned constructed structures made by M/s PMKG Techno-Management Consultancy LLP assessed are as follows:



**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

<b>Warehouse-1</b>			
The inspected property (warehouse 1) is hybrid structure (masonry = PEB. the warehouse construction is completed is 2019.the construction cost of the structure is assessed based on the market analysis and inputs received from the client.			
Covered area	(a)		20,520 SqM
Unit cost of the construction of sub structure (Construction rates are as per the applicable norms and standards and client inputs)	(b)	₹1350/SqM	
Unit cost of construction of PEB- structure (rates as per market analysis)	(c)	₹1185/ SqM	
Cost of construction of sub structure (a*b)	(d)		₹2,77,02,000
Cost of construction of PEB (a*c)	(e)		₹2,43,16,200
<b>Total cost of construction (d+e)</b>	<b>(f)</b>		<b>₹5,20,18,200</b>
Cost of MEP service @5% of (f)	(g)		₹26,00,910
Construction cost f warehouse-1 incl. MEP service (f+g)	(h)		₹5,46,19,110
Depreciation 4.0% Per year for 3 years	(i)	(-) ₹65,54,293	
Total constructed value of the warehouse (h-i)	<b>A</b>		<b>₹4,80,64,817</b>
<b>SAY[A]</b>			<b>₹4,80,65,000</b>
<b>B. Warehouse - 2</b>			
The inspected property (Warehouse -2) is hybrid structure ( Masonry + PEB). Installation of MEP services is still in progress. The construction cost of the structure is assessed based on the market analysis and inputs received from the client			
Covered area	(a)		19,836sqm

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

Unit Cost Construction of Sub-Structure (Construction rates are as per the applicable norms and Standards and client inputs)	(b)	₹1350/sqm	
Unit Cost of Construction of PEB - Structure (Rates as per market analysis)	(c)	₹ 1185/sqm	
Cost of construction of Substructure (a * b)	(d)		₹ 2,67,78,600
Cast of Construction of PEB Structure (a * c)	(e)		₹ 2,35,05,660
<b>Total Cost of Construction (d + e)</b>	<b>(f)</b>		<b>₹ 5,02,84,260</b>
Cost of MEP Services @ 5 % of ( f)	(g)		₹ 11,56,638
Construction cost of Warehouse - 1 incl. MEP services (f + g )	(h)		₹5,14,40,798
Depreciation @ 4.0 %	(i)		
<b>Total Constructed Value of the Warehouse – 1 ( h - i)</b>	<b>A</b>		<b>₹ 5,14,40,798</b>
<b>SAY (B)</b>			<b>₹ 5,14,41,000</b>
<b>Total Constructed Value of warehouse- 1 and Warehouse- 2 [ A+B]</b>			<b>₹ 9,95,06,000</b>

<b>C. Warehouse - 3</b>			
<b>The inspected property (Warehouse -3)has been proposed to be hybrid structure (Masonry + PEB). Installation of structure including MEP services is Yet to be started.</b>			
<b>Proposed Covered area</b>	<b>(a)</b>		<b>15,800 sqm</b>

**Conclusion:**

Out of 3 warehouse proposed by the PP only 2 warehouses have been erected so far and project is only partially completed. No construction, what so ever, has been initiated for the Warehouse – 3. Similarly no work has been done for the landscaping, parking area, RWH pits etc. Partial construction work has been done for the MEP in the presented erected structures. STP and more water tanks are yet to be constructed so far. Based on above observations the

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

incurred cost Rs. 9.95 Cr as estimated by Mr. Pratik Kumar Gupta of M/s PMKG Techno-Management Consultancy LLP and he is authorized under section 247 of Companies Act, 2013 to act as a valuer in respect of Land and Building cases, seems to be reasonable.

**Recommendation:**

Thus a penalty amounting to 01% of the cost incurred i.e. Rs. 9.95 Cr so far may be levied on the PP. Since the Warehouse-1 is presently under operation, an additional penalty worth 0.25% (as per MoEF&CC OM dated 07/07/21, where operations have commenced without EC) may also be imposed on the suggested value.

The case was discussed in this meeting wherein committee deliberated on the issues observed during the site visit. (Report of committee is attached as Annexure-1) Committee members visited site stated that after obtaining CA valuation report dated 19/05/22, PP has further obtained valuation report from Mr. Pratik Kumar Gupta, M/s PMKG Techno-Management Consultancy LLP and he is authorized under section 247 of Companies Act, 2013 to act as a valuer in respect of Land and Building cases and according to his report dated 20/06/22, the incurred cost is estimated as Rs. 9.95 Cr. The committee further recommends that apart from the incurred cost till 20/06/22, additional penalty of 0.25% shall be imposed as PP has put warehouse-1 in operation without EC as per MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Thus after deliberations and considering the recommendations of committee visited site, SEAC recommends that in continuation to the earlier recommendations of 572<sup>nd</sup> SEAC meeting dated 19/05/22, PP may be asked to deposit bank guarantee of Rs. 11.75 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA, Penalty @ 1% of the total project cost incurred upto the date of filling of application i.e. Rs. 9.95 lakh, additional penalty of Rs. 2,48,750 as per clause 12 a.i. and 12 a.ii respectively of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act, 1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21 with other conditions as recommended in 572<sup>nd</sup> SEAC meeting dated 19/05/22.

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

सिया से प्राप्त प्रकरणों पर चर्चा

**15. Case No. – 6638/2019 Shri Rohit Kumar Agrawal, 47, Prabhat Vihar Colony, Panna Naka, Dist. Satna, MP, Prior Environment Clearance for Laterite and Ochre Mine in an area of 11.654 ha. (Laterite – 60,000 TPA, Ochre – 8,000 TPA) (Khasra No. 102P, 103P, 133P), Village - Pagar Kala, Tehsil - Birsinghpur, District Satna (MP). Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

सिया के पत्र क्रमांक 831 दिनांक 24/06/22 के द्वारा सूचित किया है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 732वीं बैठक दिनांक 20/06/22 में चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया –

*“उक्त प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी अधिकारी, सतना के पत्र क्रमांक 2482 दिनांक 05/03/2019 अनुसार वन क्षेत्र से दूरी 20 मीटर होना बताया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डब्लू.पी. 282/1995 (टी.एन.गोवर्धन विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 03/06/22 के संदर्भ में प्रकरण पुनः परीक्षण कर अनुशंसा हेतु सेक को भेजा जावे” ।*

प्रकरण को समिति के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया, समिति ने प्रकरण के परीक्षण में पाया कि आवंटित खनन क्षेत्र सरंक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क से लगा हुआ नहीं है तथा रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, उ.प्र. से 5.82 किलोमीटर की दूरी पर है । पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नोटिफिकेशन एस.ओ. क्रमांक 3573(अ) दिनांक 09/11/2017 के अनुसार रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, उ.प्र. के ईको-संसेटिव जोन की सीमा 1.00 किलोमीटर है तथा नोटिफिकेशन में उल्लेखित वे गाँव जो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य के ईको-संसेटिव जोन की सीमा में आ रहे हैं, उसमें ग्राम पगारकला (जहाँ प्रश्नाधीन खदान प्रस्तावित है) शामिल नहीं है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डब्लू.पी. 282/1995 (टी.एन.गोवर्धन विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 03/06/22 के पृष्ठ क्रमांक-10 बिंदु क्रमांक-44 (अ) अनुसार यह आदेश सरंक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क/अभ्यारण्य पर लागू होता है तथा 09 फरवरी, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों में जो गतिविधियाँ प्रतिबंधित की गई हैं, वह सरंक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य में संचालित नहीं हो सकती है ।

अतः इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डब्लू.पी. 282/1995 (टी.एन.गोवर्धन विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

**583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 30 जून 2022**

**16. Case No. – 6417/2019 Shri Rana Pratap Singh, R/o Suryanchal Garhi, VPO Ghuwara, Dist. Chhatarpur, MP. Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 18.21 ha. (77,010 TPA) (Khasra No. 1008), Village - Tigoda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP).**

सिया के पत्र क्रमांक 833 दिनांक 24/06/22 के द्वारा सूचित किया है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 732वीं बैठक दिनांक 20/06/22 में चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया –

*“वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्रमांक 2595 दिनांक 07/10/2015 अनुसार वन क्षेत्र से दूरी 444 मीटर होना बताया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डब्लू.पी. 282/1995 (टी.एन.गोवर्धन विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 03/06/22 के संदर्भ में प्रकरण पुनः परीक्षण कर अनुशंसा हेतु सेक को भेजा जावे” ।*

प्रकरण को समिति के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया, समिति ने प्रकरण के परीक्षण में पाया कि आवंटित खनन क्षेत्र सरंक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क/अभ्यारण्य से लगा हुआ नहीं है । इसलिए इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डब्लू.पी. 282/1995 (टी.एन.गोवर्धन विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

### **Annexure- 'A'**

#### **Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 30 जून 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.  
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream



## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 30 जून 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 30 जून 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - i. Minable Potential of sand mine.
  - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
  31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

### नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

### Annexure- 'C'

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 30 जून 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
  15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
  16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
  17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
  18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
  19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
  20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
  21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
  22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
  23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - I. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    - o. Minalable Potential of sand mine.
    - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
  27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 30 जून 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

## 583वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 जून 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained